दिलो-दिमाग पर पड़ा असर

कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने सामान्य जीवन को जिस तरह से तहस-नहस कर दिया था, उसे देखते हुए यह आम धारणा थी कि कमजोर दिल-दिमाग वाले लोगों के लिए इसे सहन करना खासा मुश्किल रहा होगा।

आरती सिंह।।

नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी किए गए साल 2020 के दौरान आत्महत्या और दुर्घटना में हुई मौतों के आंकड़े इस लिहाज से भी अहम हैं कि पहली बार इनसे कोरोना के आम लोगों के जीवन और खासकर उनके दिलो-दिमाग पर पड़े असर की पुष्टि होती है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने सामान्य जीवन को जिस तरह से तहस-नहस कर दिया था, उसे देखते हुए यह आम धारणा थी कि कमजोर दिल-दिमाग वाले लोगों के लिए इसे सहन करना खासा मुश्किल रहा होगा। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के मामलों में 2019 के मुकाबले इस साल 10 फीसदी इजाफा हुआ है। 2020 में आत्महत्या से कुल 153,053 मौतें हुई हैं, जो 1967 के बाद से सबसे ज्यादा हैं। आत्महत्या करने वाले इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या (24.6 फीसदी) दिहाड़ी पर काम करने वालों की है। लॉकडाउन का सबसे मारक प्रभाव इन्हीं लोगों की आजीविका पर पड़ा था। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित तबके के रूप में उभरते हैं स्टूडेंट्स। अमूमन हर साल खुदकुशी करने वालों में स्टूडेंट्स 7-8 फीसदी होते हैं, लेकिन साल 2020 में इनका प्रतिशत 21.2 दर्ज किया गया है। असल में, लॉकडाउन के कारण जिस तरह से अचानक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, उसका बच्चों पर जबर्दस्त असर पड़ा। न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई बल्कि स्कूल-कॉलेज का माहौल छूट गया, दोस्तों से मिलना-जुलना बंद हो गया और उनका पूरा जीवन घर की चारदीवारी तक सिमट कर रह गया। 68 दिन लंबे लॉकडाउन के बाद जीवन के अन्य क्षेत्र धीरे-धीरे खुलना शुरू भी हुए, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद ही रहे। इस बीच ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई का सिलसिला शुरू भी हुआ तो उन बच्चों की हताशा और बढ़ गई जिनकी डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं थी। और, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं थी। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2.9 करोड़ स्टूडेंट्स स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि उपकरणों तक पहुंच न होने के चलते पढ़ाई की व्यवस्था से कट गए थे। वैसे इन सबके बीच ही लॉकडाउन का एक पॉजिटिव पहलू यह रहा कि साल 2020 में सड़क हादसों से होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी नीचे आया। इस साल सड़क हादसों में कुल 374,397 मौतें हुईं , जो 2019 के मुकाबले 11.1 फीसदी कम हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़े एक ऐसी चुनौती से गुजरने के निशान बयां करते हैं जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं था और जिससे हम अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। बहरहाल, इन आंकड़ों की रोशनी में नीतियों को काट-छांट कर ज्यादा उपयुक्त, ज्यादा सटीक बनाने का काम बेहतर ढंग से हो सकता है।

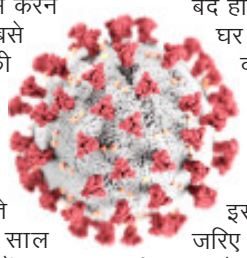

स्वयंबर का निर्णय

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

योगी ने जयमाला निकालकर राजकुमारी को दे दी। चारों तरफ घूमकर राजकुमारी ने जयमाला दूसरी बार भी योगी के गले में डाल दी और ऐसा ही तीसरी बार भी हुआ। आखिर स्वयंबर में उपस्थित राजकुमारों ने कहा कि अब राजकुमारी का विवाह योगी के साथ ही होगा।

स्वयंबर का निर्णय सुनकर योगी वहां से भाग निकला। राजकुमारी ने योगी का पीछा किया। आगे आगे योगी, उसके पीछे राजकुमारी और अंत में राजा श्यामसिंह। भागते भागते योगी और राजा घने जंगल में पहुंचे। कुछ दूर और पीछा करने के बाद राजकुमारी आगे न जा सकी। शीत ऋतु थी, धीरे धीरे पानी बरस रहा था, रात भी अंधेरी। आगे चलने का उचित समय न रहने के कारण राजा और योगी एक शाल्मली के वृक्ष के नीचे बैठ गए।

संपादकीय

वोट बैंक की मजबूरी

सच है कि राममंदिर आंदोलन के उभार के दिनों से ही संघ परिवार अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा के भी मामलों का जिक्र करता रहा है। इसलिए यह मान लेना कि संघ विचार परिवार की राजनीति इससे इतर हो जाएगी, नादानी ही कही जाएगी। वैसे भी बीजेपी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो अक्सरहां उससे इन मुद्दों पर राय जानने की कोशिश करता रहता है। पार्टी को इन मुद्दों के प्रति आग्रही अपने वोटरों के साथ भी रिश्ता रखना है, इसलिए वह मथुरा जैसे मुद्दों को छोड़ नहीं सकती। मथुरा के मुद्दे को उठाने की एक वजह बीजेपी के लिए अपने प्रतिबद्ध वोटरों के रुझान को अभिव्यक्ति देना तो है ही, मौजूदा राजनीति में खुद प्रासंगिक बने रहना भी है। अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर को अपवाद माना गया है। ऐसे में मौर्य के बयान पर स्वाभाविक ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शासन में जिम्मेदारी के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। अपने कोर वोटरों को जोड़े रखने के लिए जहां ऐसे कोर मुद्दों पर बीजेपी को बने रहना होगा, वहीं विकास के मुद्दे पर भी आक्रामक राजनीति करनी होगी। केशव प्रसाद मौर्य के हालिया ट्वीट को इन तथ्यों के संदर्भ में समग्रता से देखा जाना चाहिए।

साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी ने 18 साल पहले चुनावी राजनीति के लिए विकास के मुद्दे को पहले पायदान पर रखना शुरू किया था। साल 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भी विकास को सबसे ऊपर रखा था।

विकास पर जोर

उमेश चतुर्वेदी।।

चुनाव के ठीक पहले सियासी मैदान के शूरमाओं की ओर से बयान आएं तो उनके राजनीतिक अर्थ निकाले ही जाएंगे। अगर बयान आबादी के लिहाज से सबसे बड़े और राजनीति के हिसाब से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो तो उसका विश्लेषण कुछ ज्यादा ही होगा। यहां प्रसंग उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है।'

याद किया जा सकता है कि साल 2003 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने एक नई परिपाटी डालने की कोशिश की थी। तब केंद्र में वाजपेयी की अगुआई वाली सरकार थी। उस वक्त बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार प्रमोद महाजन ने तीनों राज्यों के चुनावों के लिए 'बीएसपी' को मुद्दा बताया था। बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी।

साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी ने 18 साल पहले चुनावी राजनीति के लिए विकास के मुद्दे को पहले पायदान पर रखना शुरू किया था। साल 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भी विकास को सबसे ऊपर रखा था। हालांकि बीजेपी के अब तक के उभार में राम मंदिर आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रही है।

हर चुनाव में कमोबेश वह इस मुद्दे के इर्द-गिर्द रहती भी आई है। लेकिन हाल के कुछ चुनावों में बीजेपी ने प्रमुखता से सिर्फ विकास का मुद्दा उठाया है। हिंदुत्व और राममंदिर से जुड़े मुद्दों को उसने उनके बाद ही रखा है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब मथुरा का मुद्दा उठाया तो उसके पीछे के अर्थ तलाशे जाने लगे।

साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की दुनिया में लंबी यात्रा तय की है। धीरे-धीरे वह बीजेपी की राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी आलाकमान ने उनके हाथों राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाकर एक तरह से उनकी अहमियत को ही स्थापित करने की कोशिश की है। इन सबके बावजूद एक सच यह भी है कि साल 2017 की उत्तर प्रदेश की जीत के एक स्तंभ केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। उन दिनों पार्टी के वही अध्यक्ष थे। इस नाते मुख्यमंत्री पद पर उनकी निगाह भी रही ही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वह पिछड़ गए। बेशक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में उन्हें नंबर दो का पद हासिल हुआ है, लेकिन शायद उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। कुछ राजनीतिक जानकार मौजूदा दौर को हिंदुत्व का नवजागरण काल मानते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहते रहे हैं कि बहुसंख्यक वैचारिकी के उभार की वजह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति रही है। नैरेटिव केंद्रित राजनीति का भी हिंदुत्व दर्शन और विचार की बुनियाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा विश्वहिंदू परिषद के दिग्गज अशोक सिंघल की छत्रछाया में शुरू हुई और आगे बढ़ी। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मौर्य इन तथ्यों को अच्छी तरह समझते होंगे। मंडल आयोग के बाद राजनीति जिस तरह पिछड़ावाद की ओर उन्मुख हुई है, उसकी वजह से विभिन्न दलों में स्वाभाविक रूप से पिछड़े वर्गों से राजनीतिक नेतृत्व उभरा। कई दलों ने सायास तरीके से भी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को उभारने की कोशिश की। इस प्रक्रिया से बीजेपी भी अलग नहीं है। इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखता है।

सूडोकु नवताल-5242

सरल

3	9				1			
5	4			6	8		1	3
		1		7		9	5	
	8	9		5	3		4	7
6	1		4	9		2	3	
	3	4		1		8		
7	5		8	3			2	4
			6				7	9

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5241 का हल

9	6	2	3	4	1	7	5	8
1	4	8	9	7	5	6	2	3
5	7	3	2	6	8	1	4	9
3	2	1	6	9	4	8	7	5
4	8	7	5	1	2	9	3	6
6	9	5	8	3	7	4	1	2
8	3	4	7	2	6	5	9	1
2	1	6	4	5	9	3	8	7
7	5	9	1	8	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

चुनाव बाद के नए समीकरण

मोहन। गैर-यादव पिछड़ी जातियों में बीजेपी की गहरी पैठ इसका ठोस उदाहरण है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। इसलिए अगर चुनाव बाद के नए समीकरणों में उन्हें अपने लिए अवसर दिखता है तो उसमें कुछ असामान्य भी नहीं है। बेशक अभी तक उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चुनौती नजर नहीं आती। लेकिन बीजेपी में ही असम का भी उदाहरण है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की ही अगुआई में पार्टी की असम में जीत हुई। लेकिन चुनाव बाद उनकी जगह हिमंता बिस्वसर्मा को कमान मिल गई। कुछ राजनीतिक समीक्षक इस संदर्भ में भी केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को देख रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1991 का पूजास्थल कानून अब भी बरकरार है, जो कहता है कि आजादी के समय देश के पूजास्थलों की धार्मिक अवस्थिति थी, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।